

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 79] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 1, 1990/फाल्गुन 10, 1911
No. 79] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 1, 1990/PHALGUNA 10, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(विदेश कर प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1990

आयकर

उपाबंध

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व
अपवर्जन को रोकने के लिए

भारत गणराज्य की सरकार और जापान की सरकार के बीच अभिसमय
भारत गणराज्य की सरकार और जापान की सरकार, आय पर करों
के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवर्जन को रोकने
के लिए एक नया अभिसमय सम्पन्न करने की इच्छा से, नीचे लिखे अनुसार
सहमत हुई है :

सा.का.नि. 101 (अ) :- दोहरे कराधान का अपवर्जन करने के
लिए और आय पर करों की बाबत राजवित्तीय अपवर्जन को रोकने के लिए,
भारत गणराज्य की सरकार और जापान सरकार के बीच इससे उपाबद्ध
कन्वेंशन के अनुच्छेद 28 के पैरा 1 की अपेक्षानुसार अनुसमर्थन की लिखत
के आदान-प्रदान के पश्चात् 29 दिसम्बर, 1989 को प्रवृत्त हो गया है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961
का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह
निर्देश देती है कि उक्त कन्वेंशन के सभी उपाबंधों को भारत संघ में प्रभावी
किया जाएगा।

अनुच्छेद 1

यह अभिसमय उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो दोनों सम्बन्धित
राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों राज्यों के निवासी हैं।

अनुच्छेद 2

1 जो कर इस अभिसमय के विषय हैं, वे इस प्रकार हैं :-

(क) जापान में :

(i) आयकर ; और

(ii) निगम कर

(इन्हें इसके बाद “जापानी कर” कहा गया है) ;

(ख) भारत में :

अथवा, जिसमें उस पर, लगाया गया कोई अधिभार भी शामिल है ।

(जिसे इसके बाद “भारतीय कर” कहा गया है) ।

2. यह अधिसमय किसी भी समरूप अथवा मारत: इसी तरह के करों पर भी लागू होगा, जो इस अधिसमय पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख के पश्चात् पैराग्राफ 1 में उल्लिखित करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर लगाए जाएंगे। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी किन्हीं भी महत्वपूर्ण परिवर्तनों के संबंध में, ऐसे परिवर्तनों के पश्चात् एक समुचित अवधि के भीतर, एक दूसरे को सूचित करेंगे जो उनके अपने-अपने कराधान कानूनों में किए गए हों ।

अनुच्छेद 3

1. इस अधिसमय के प्रयोजनों के लिए जब तक कि विषयगत पाठ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) “जापान” शब्द से अभिप्रेत है जब एक भौगोलिक उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है तो इसका अर्थ है जापान का राज्य क्षेत्र जिसमें यह भी शामिल है—राज्य क्षेत्रीय समुद्र जिम पर जापानी कर से संबंधित कानून लागू होता है, राज्य क्षेत्रीय समुद्र से परे समस्त क्षेत्र जिसमें उसका समुद्रतल तथा अवमृदा भी शामिल है, जिस पर जापान अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार क्षेत्राधिकार रखता है तथा जिसमें जापानी कर से संबंधित कानून प्रवृत्त हैं ;

(ख) “भारत” शब्द से अभिप्रेत है—भारत का राज्य क्षेत्र और उसमें शामिल है—राज्य क्षेत्रीय समुद्र तथा कोई भी अन्य समुद्री क्षेत्र जिसके बारे में भारत को भारतीय कानून के अनुसार तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार प्राप्त है ;

(ग) “एक संविदाकारी राज्य” तथा “दूसरा संविदाकारी राज्य” पदों से विषयगत पाठ की अपेक्षा के अनुसार जापान अथवा भारत अभिप्रेत है ;

(घ) “कर” शब्द से विषयगत पाठ की अपेक्षा के अनुसार जापानी कर अथवा भारतीय कर अभिप्रेत है ;

(ङ) “व्यक्ति” शब्द में कोई व्यक्ति, कोई कम्पनी और व्यक्तियों का कोई अन्य निकाय शामिल है ;

(च) “कम्पनी” शब्द से कोई भी ऐसा निगमित निकाय अथवा कोई सत्ता अभिप्रेत है जिसे कर-प्रयोजनों के लिए एक निगमित निकाय के रूप में माना जाता है ;

(छ) “एक संविदाकारी राज्य का उद्यम” और “दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम” पदों से क्रमशः एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत है ;

(ज) “राष्ट्रिक” शब्द से अभिप्रेत है :-

(i) जापान के बारे में :

सभी व्यक्ति जिन्हें जापान की राष्ट्रिकता प्राप्त है और सभी विधिक व्यक्ति जिनका सृजन अथवा संगठन जापान के कानूनों के अंतर्गत हुआ हो तथा ऐसे सभी विना विधिक व्यक्तित्व वाले संगठन जिन्हें जापान के कानूनों के अंतर्गत जापानी कर के प्रयोजनार्थ सृजित अथवा संगठित किए गए विधिक व्यक्तियों के रूप में माना गया हो ।

(ii) भारत के बारे में :

(क) ऐसे सभी व्यक्ति जिन्हें भारत की राष्ट्रिकता प्राप्त हो ;

(ख) ऐसे सभी विधिक व्यक्ति भागीदारिता तथा मंभ जिन्हें भारत में प्रवृत्त कानूनों से इस तरह की हैसियत प्राप्त हो ,

(झ) “अन्तर्राष्ट्रीय यातायात” पद से अभिप्रेत है - किसी ऐसे जलयान अथवा वायुयान द्वारा कोई भी परिवहन जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा संचालित हो सिवाय उस स्थिति के जब उक्त जलयान अथवा वायुयान केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के स्थानों के बीच हो चलाया जाता हो ; और

(ञ) “सक्षम प्राधिकारी ” पद से अभिप्रेत है :

(i) जापान में, वित्त मंत्री अथवा, उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि ;

(ii) भारत में, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में केन्द्रीय सरकार अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि ।

2. जहाँ तक किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इस अधिसमय के प्रवर्तन का संबंध है, किसी शब्दावली का जो उसमें परिभाषित नहीं हुई हो, जब तक विषयगत पाठ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो, तब तक वही अर्थ होगा जो उस संविदाकारी राज्य के करों से संबंधित कानूनों के अन्तर्गत होता है जिन पर ये अधिसमय लागू होता है ।

अनुच्छेद 4

1. इस अधिसमय के प्रयोजनार्थ, “किसी संविदाकारी राज्य का निव.सी” पद से अभिप्रेत है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पर, उस राज्य के कानून के अन्तर्गत उसके अधिवास, निवास, प्रबंध-स्थान अथवा इस प्रकार की किसी भी अन्य कसौटी के कारण वहाँ पर कर लगाया जा सकता है ।

2. जहाँ पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निव.सी हो, वहाँ संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी परस्पर सहमति से उस संविदाकारी राज्य का निर्धारण करेंगे जिस राज्य का वह व्यक्ति इस अधिसमय के प्रयोजनार्थ एक निवासी समझा जाएगा ।

अनुच्छेद 5

1. इस अधिसमय के प्रयोजनार्थ “स्थायी संस्थापन” पद से कारोबार का वह निश्चित स्थान अभिप्रेत है, जहाँ किसी उद्यम का कारोबार सम्पूर्णतः अथवा अंशतः चलाया जाता है ।

2. “स्थायी संस्थापन” पद के विषयगत निम्नलिखित शामिल होंगे :-

(क) प्रबंध व्यवस्था का कोई स्थान ;

(ख) कोई शाखा ;

(ग) कोई कार्यालय ;

(घ) कोई कारखाना ;

(ङ) कोई कार्यशाला ;

(च) कोई खान, तेल अथवा गैस या कोई कुआँ कोई खदान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान ;

(छ) कोई भाण्डागार जिसमें कोई व्यक्ति दूसरों के लिए भाण्डारण सुविधाएँ मुहैया करता हो ;

(ज) कोई फार्म, बगीचा अथवा अन्य स्थान जहाँ पर कृषि, वानिकी पौधे उगाने अथवा उनसे संबंधित कार्यकलाप किए जाते हों ,

(झ) कोई झण्डार अथवा अन्य बिजली कोष्ठ ; तथा

(ज) कोई संस्थापना अथवा संरचना जिसका इस्तेमाल प्राकृतिक संसाधनों की खोज के लिए किया जाता हो, किन्तु केवल उस स्थिति में जब उसका इस्तेमाल छः महीने की अवधि से अधिक समय तक किया गया हो।

3. कोई भवन स्थल अथवा निर्माण, संस्थापना अथवा एसेम्बली प्रोजेक्ट केवल उस स्थिति में कोई स्थायी संस्थापन होगा यदि वह छः महीने से अधिक समय तक विद्यमान रहता है।

4. किसी उद्यम का किसी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन का होना और उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार का चलाया जाना तभी समस्या जाएगा यदि वह उस संविदाकारी राज्य में किसी निर्माणस्थल अथवा निर्माण, संस्थापना अथवा ऐसे एसेम्बली प्रोजेक्ट के संबंध में छः महीने की अवधि से अधिक समय तक पर्यवेक्षी कार्यकलाप चलाता हो जो उस संविदाकारी राज्य के भीतर शुरू किए जाते हों।

5. पैराग्राफ 3 तथा 4 के उपबंधों के होते हुए भी किसी उद्यम का किसी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन का होना और उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार का चलाया जाना तभी माना जाएगा यदि वह उस संविदाकारी राज्य में उस संविदाकारी राज्य के अंतर्गत खनिज तेलों की खोज, उनके मनुयोजन अथवा निष्कर्षण के बारे में छः महीने की अवधि से अधिक समय के लिए सेवाएं अथवा सुविधाएं प्रदान करता है।

6. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती पैराग्राफों के उपबंधों के होते हुए भी "स्थायी संस्थापन" पद से निम्नलिखित का शामिल नहीं होना माना जाएगा :

(क) उस उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य वस्तुओं के भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ माल सुविधाओं का इस्तेमाल करना;

(ख) माल भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ उस उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य वस्तुओं के किसी स्टॉक का रख-रखाव करना;

(ग) माल किसी अन्य उद्यम द्वारा संसाधित किए जाने के प्रयोजनार्थ उस उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य वस्तुओं के किसी स्टॉक का रख-रखाव करना;

(घ) उस उद्यम के लिए माल अथवा पण्य वस्तुओं की मात्र खरीद करने अथवा उसके बारे में सूचना एकत्र करने के लिए व्यापार के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना;

(ङ) उस उद्यम के लिए माल किसी प्रारंभिक अथवा सहायक किस्म के किसी अन्य कार्यकलाप को चलाने के प्रयोजनार्थ व्यापार के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना।

7. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबंधों के होते हुए भी जहां पर कोई स्वतंत्र हैसियत के किसी एजेंट, जिस पर पैराग्राफ 8 लागू होता हो, से भिन्न कोई व्यक्ति दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम को तरफ से किसी संविदाकारी राज्य में कार्य करता हो, उस उद्यम का प्रयोनो-लिखित संविदाकारी राज्य में किसी स्थायी संस्थापन का होना तभी माना जाएगा :

(क) यदि उसे उस उद्यम की तरफ से उस संविदाकारी राज्य में ठेकों को सम्पन्न करने का अधिकार प्राप्त हो तथा वह आदतन ऐसे ठेके सम्पन्न करता हो, जब तक कि इसके कार्य कलाप, यदि उन्हें कारोबार के किसी निश्चित स्थान पर सम्पन्न किया गया हो, पैराग्राफ 6 में उल्लिखित कार्यकलापों तक सीमित नहीं हों, जिसके द्वारा कारोबार का यह निश्चित स्थान उस पैराग्राफ के उपबंधों के तहत एक स्थायी संस्थापन नहीं बनेगा;

(ख) उसके पास इस तरह का कोई प्राधिकार नहीं हो किन्तु वह प्रयोनो-लिखित संविदाकारी राज्य में ऐसे माल अथवा पण्य वस्तुओं का एक स्टॉक आदतन रखता हो जिसमें से वह निश्चित रूप से इस उद्यम को तरफ से माल अथवा पण्य वस्तुओं को डिलीवरी करता हो; अथवा

(ग) वह उस प्रयोनो-लिखित संविदाकारी राज्य में आदतन आदेश प्राप्त करता हो, पूर्णतः अथवा लगभग पूर्णतः स्वयं उस उद्यम के लिए अथवा उद्यम के लिए और ऐसे उद्यमों के लिए जो नियंत्रण रखते हों, नियंत्रण में रहने हों, अथवा उस उद्यम की तरह उस जैसे नियंत्रण में रहते हों।

8. किसी उद्यम का किसी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन का होना माल इस कारण नहीं माना जाएगा कि वह किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेंट अथवा किसी स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेंट की मर्कत उस संविदाकारी राज्य में व्यापार चलाता हो बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार की सामान्य प्रक्रिया में कार्य करते हों।

9. इस तथ्य से कि कोई कम्पनी जो किसी संविदाकारी राज्य का निवासी है किसी ऐसे कम्पनी पर नियंत्रण रखती अथवा उसके द्वारा नियंत्रित होती जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी हो अथवा जो दूसरे संविदाकारी राज्य में (चहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) कारोबार चलाता हो, दोनों में से किसी भी कम्पनी को दूसरी कम्पनी का स्थायी संस्थापन का दर्जा नहीं देता।

अनुच्छेद 6

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. "अचल सम्पत्ति" पद का अर्थ हो होगा जो उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत उसका अर्थ है जिसमें संबंध सम्पत्ति स्थित है। इस पद में किसी भी दशा में ये शामिल होंगे—अचल सम्पत्ति के अवसाधन के रूप में सम्पत्ति, कृषि और वनिकी में प्रयुक्त पशुधन और उपस्कर, ऐसे अधिकार जिन पर अचल सम्पत्ति तबवी सामान्य कानून के उपबल लागू होते हों, अचल सम्पत्ति को भोगने का अधिकार और खनिज भण्डारों, स्त्रोतों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संचालन के लिए, अथवा कार्य के अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा निवृत्त अदायगियों के अधिकार; जलयान तथा वायुयान अचल सम्पत्ति नहीं माने जाएंगे।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंध अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, उसे किराए पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार के उपयोग से होने वाली आय पर भी लागू होंगे।

4. पैराग्राफ 1 तथा 3 के उपबंध किसी उद्यम की अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर तथा स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर भी लागू होंगे।

अनुच्छेद 7

1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभों पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उस राज्य में कारोबार नहीं करता हो। यदि वह उद्यम उन्मुख तरीके से कारोबार चलाता हो तो उस उद्यम के लाभों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकता है, किन्तु उसके लाभों के केवल उतने अंश पर ही कर लगाया जा सकेगा जो प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः उस स्थायी संस्थापन के कारण हो।

2. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अर्थात् रहने हुए जहाँ एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के समक्ष से करोड़ों चलत हो, ता प्रत्येक संविदाकारी राज्य में ऐसे लाभों को उस स्थायी संस्थापन के लाभ समझा जाएगा जो उस स्थिति में प्राप्त होने का अपेक्षा रहता जब वह एक समान अथवा उससे मिलती-जुलती परिस्थितियों में एक समान या उद्देश्यमिलने-जुलते कार्यकलापों में लगा हुआ कोई निश्चित और निश्चित उद्यम होता और उस उद्यम के साथ पूर्णतया स्वतंत्र रूप से करोड़ों करत। जिसका यह एक स्थायी संस्थापन है ।

3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण करने में उन उच्चों को कटौतियों के रूप में अनुमति दी जाएगी जो उस स्थायी संस्थापन के कारोबार के प्रयोजनार्थ किए गए हों, जिनमें इस प्रकार से किए कार्यकारी तथा सामान्य प्रशासनिक उच्चों भी शामिल हों, चहे वे उस राज्य में किए गए हों जहाँ वह स्थायी संस्थापन स्थित है अथवा अन्वय किए गए हों ।

4. जहाँ किसी संविदाकारी राज्य में यह प्रथा रही है कि किसी स्थायी संस्थापन को होने वाले लाभों का निर्धारण उद्यम के कुल लाभों को उसके विभिन्न भागों में विभाजन के आधार पर किया जाता हो, वहाँ पैराग्राफ 2 की कोई भी बात उस संविदाकारी राज्य की प्रथा अनुसार विभाजन के द्वारा कर-योग्य लाभों का निर्धारण करने से निर्धारित नहीं करेगी; तथापि विभाजन के लिए अपनाई गई विधि ऐसी होगी कि उसके परिणाम इस अनुच्छेद में विहित सिद्धान्तों के अनुकूल होंगे ।

5. कोई भी ऐसा लाभ मात्र इस कारण से किसी स्थायी संस्थापन को प्राप्त हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के लिए माल अथवा पण्य वस्तुएं खरीदी गई हैं ।

6. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती पैराग्राफों के उपबंधों के प्रयोजनार्थ स्थायी संस्थापन के कारण उत्पन्न हुए समझे जाने वाले लाभों का तब तक वर्णानुवर्ण उसी पद्धति से निर्धारण किया जाता रहेगा जब तक कि उसके विपरीत उचित तथा पर्याप्त कारण नहीं हों ।

7. जहाँ पर लाभों में आय की ऐसी मदें शामिल हैं जिनका इस अभिसमय के अन्य अनुच्छेदों में अलग से विवेचन किया गया है, वहाँ पर उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुच्छेद के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे ।

अनुच्छेद 8

1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में वायुयान के परिचालन से प्राप्त लाभों पर उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जाएगा ।

2. किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में वायुयानों के न से प्राप्त लाभों पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगेगा ।

3. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के होते हुए भी, ऐसे लाभों पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगेगा जहाँ से कराधेय प्रथम दस वर्षों की अवधि के दौरान अथवा "पूर्ववर्ती वर्षों" में, जैसा भी मामला हो, प्राप्त हुए हों, जिस अवधि के लिए यह अभिसमय प्रभाव होना बशर्त कि इस प्रकार प्रभाति कर की सीमा निम्नलिखित से अधिक नहीं हो ;

(क) प्रथम पांच वर्षों के दौरान, 50 प्रतिशत ;

(ख) शेष पांच वर्षों के दौरान, उस दूसरे संविदाकारी राज्य के कराधान कानून के द्वारा अथवा लगाए गए कर की मात्रा का 25 प्रतिशत ।

4. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती पैराग्राफों के उपबंध किम पूल, किसी संयुक्त कारोबार अथवा किसी अन्तरराष्ट्रीय एजेंसी में भागधारिता से प्राप्त लाभों पर भी लागू होंगे ।

5. अनुच्छेद 2 के उपबंधों के होते हुए भी, इस अनुच्छेद के उपबंध जापान में उद्यम कर पर भी लागू होने के साथ-साथ उस उद्यम कर से मिलने-जुलते किसी कर पर भी उस स्थिति में लागू होंगे जहाँ कभी ऐसा कर भारत में लगाया गया हो ।

अनुच्छेद 9

1. जहाँ :

(क) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम को प्रबंध व्यवस्था, नियंत्रण अथवा पूँजी के सन्निधि में प्रत्यक्षः अथवा अप्रत्यक्षः भाग लेता है, अथवा

(ख) वही व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम को प्रबंध व्यवस्था, नियंत्रण अथवा पूँजी के सन्निधि में प्रत्यक्षः अथवा अप्रत्यक्षः भाग लेने हैं ;

दोनों ही अवस्थाओं में, दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखा अथवा लगाई जातों हों, जो ऐसी शर्तों से भिन्न हों जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखा जातों हों, तो ऐसा कोई भी लाभ जो उन शर्तों के नहीं होने की दशा में दोनों उद्यमों में से किसी एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता परन्तु उन शर्तों के कारण वह इस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ हो, उस उद्यम के लाभों में सम्मिलित किया जा सकेगा और तदनुसार कर लगाया जा सकेगा ।

2. जहाँ पर एक संविदाकारी राज्य उस संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभों में उन लाभों को सम्मिलित करता है और तदनुसार कर लगाता है—जिन पर दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया गया है और जहाँ पर संविदाकारी राज्यों के मध्य प्राधिकारों विचार-विमर्श करने के पश्चात् इस बात पर सहमत होते हैं कि इस प्रकार समाहित किए गए कुल लाभ अथवा लाभों का कोई अंग ऐसे लाभ हैं जो प्रयोजनार्थ संविदाकारी राज्य के उस उद्यम को उस स्थिति में प्राप्त हुए होते यदि दोनों उद्यमों के बीच बनाई गई शर्तें इस तरह कहती जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच बनाई गई होतीं तो वह दूसरा संविदाकारी राज्य उस तरह से सहमति प्राप्त लाभों पर, उन पर प्रभाति कर की मात्रा के अनुसार समुचित समायोजन करेगा । इस तरह का समायोजन करने में इस अभिसमय के अन्य उपबंधों पर यथोचित ध्यान रखा जाएगा ।

अनुच्छेद 10

1. किसी एक संविदाकारी राज्य को निवासों कम्पनी उसके द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासों को अदा किए गए लाभांश उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कराधेय होंगे ।

2. तथापि, इस प्रकार के लाभांश उस संविदाकारी राज्य में भी कराधेय होंगे, जिसको लाभांश अदा करने वाली कम्पनी उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार वहाँ निवासी है लेकिन यदि प्राप्तकर्ता लाभांशों का हितभोगी स्वामी है, तो इस प्रकार के प्रभाति कर की रकम उक्त लाभांशों का सकल रकम के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

इस पैराग्राफ के उपबंध उस कम्पनी के उन लाभों से संबंधित कराधान को प्रभाति नहीं करे, जिनमें से लाभांशों का भुगतान किया जाना है ।

3. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "लाभांशों" शब्द का अभिप्राय है—शेयरों अथवा अन्य अधिकारों से, जो ऋण-दावे नहीं हों, जो लाभ में शामिल हों, प्राप्त आय, तथा अन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त आय जिस पर उद्यम प्रकार को कराधान व्यवस्था लागू होती है जो उस संविदाकारी राज्यों के कानूनों द्वारा शेयरों से प्राप्त आय के मामले में लागू होती है जिसमें वितरण करने वाली कम्पनी निवासी है ।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के अन्तर्गत उक्त स्थिति में जहाँ जहाँ यह है कि लाभांशों का हिस्सा स्वामी, जो किसी एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में वहाँ स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से व्यापार करता है, जिसको लाभांश अदा करने वाले कंपनी निवासी है, अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में वहाँ स्थित किया निश्चित स्थान से स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं सम्पन्न करता है और जिस सम्पत्ति के संबंध में लाभांशों को अदायोगों को जाना है वे इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावों रूप से सम्बद्ध हैं। ऐसे मामलों में, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 जैसा भी मामला हो, के संबंध लागू होंगे।

5. जहाँ कोई कम्पनी, जो किसी संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य के लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, ऐसे मामले में उस कंपनी द्वारा अदा किए गए लाभांशों पर जहाँ तक ऐसे लाभांशों को छोड़कर, जो दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए हों, अथवा जहाँ तक कि ऐसे सम्पत्ति के बारे में लाभांशों को अदायोगों की गई हो, जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावों रूप से सम्बद्ध है, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में न तो कोई कर लगाया जाएगा और न ही कंपनी के अवितरित लाभों पर अवितरित लाभकर को किसी का कोई कर लगाया जाएगा, भले ही अदा किए गए लाभांश अथवा अवितरित लाभ पूर्णतः अथवा अंशतः उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में हो हों।

अनुच्छेद 11

1. किसी संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को अदा किए जाने वाले ब्याज पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगेगा।

2. तथापि, इस प्रकार के ब्याज पर संविदाकारी राज्य में भी और उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगेगा, जिस राज्य में यह उद्भूत होता है किन्तु यदि प्राप्तकर्ता ब्याज का हिस्सा स्वामी है तो इस प्रकार प्रभावित कर को राशि निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी :

(क) ब्याज को सकल राशि का 10 प्रतिशत, यदि हिस्सा स्वामी बैंक है ; और

(ख) सभी अन्य मामलों में ब्याज को सकल राशि का 15 प्रतिशत।

3. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के होते हुए भी किन्तु एक संविदाकारी राज्य में दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार, उसके राजनीतिक उपयोग अथवा स्थानीय प्राधिकरण, दूसरे संविदाकारी राज्य के केन्द्रीय बैंक अथवा उस सरकार के पूर्णतः स्वामित्व वाले किसी वित्तीय संस्था द्वारा गारंटीशुदा अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वित्त-पोषित ऋण-दायकों के संबंध में उद्भूत तथा उस दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार, उसके राजनीतिक उपयोग अथवा स्थानीय प्राधिकरण, उस दूसरे राज्य के केन्द्रीय बैंक अथवा उस सरकार के पूर्णतः स्वामित्व वाले किसी वित्त संस्था द्वारा अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा प्राप्त ब्याज को प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी।

4. पैराग्राफ 3 के प्रयोजनार्थ, "केन्द्रीय बैंक" तथा "सरकार के पूर्णतः स्वामित्व वाली वित्तीय संस्था" पद का अभिप्राय :

(क) जापान के मामले में :

- (1) दि बैंक आफ जापान
- (2) जापान का नियति-यायात बैंक ;
- (3) समुद्रासीय आर्थिक सहयोग निधि ;
- (4) जापान अन्तरराष्ट्रीय सहयोग अभिकरण; और

(5) ऐसी अन्य वित्तीय संस्था, जिसको पूंजी का स्वामित्व पूर्णतया जापान सरकार द्वारा धारित हो, जो दोनों संविदाकारी राज्यों की सरकारों के बीच समय-समय पर सहमत हो ;

(ख) भारत के मामले में :

(1) भारतीय रिजर्व बैंक ;

(2) भारत का नियति-यायात बैंक ;

(3) ऐसी अन्य वित्तीय संस्था, जिसको पूंजी भारत सरकार द्वारा पूर्णतया धारित हो तथा दोनों संविदाकारी राज्यों की सरकारों के बीच समय-समय पर सहमत हों।

5. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "ब्याज" शब्द से अभिप्रेत है— प्रत्येक प्रकार के ऋण-दानों में प्राप्त आय, चाहे वे बंधक द्वारा प्रतिभूत हों या नहीं हों, और चाहे ऋण-दान के लाभों में भागोदारी का कोई अधिकार रखने हों या नहीं रखते हों, और खासतौर पर, गारंटी प्रतिभूतियों से प्राप्त आय और बंधपत्रों अथवा ऋण-पत्रों से प्राप्त आय, जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों, बंधपत्रों अथवा ऋण-पत्रों से संबंधित प्राप्तिमय और पुरस्कार भी शामिल हैं।

6. पैराग्राफ 1, 2 और 3 के अन्तर्गत उक्त स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि ब्याज का हिस्सा स्वामी, जो किसी संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में जिसमें ब्याज, प्रतिभूत हुआ हो, वहाँ स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार चलाता है अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में वहाँ स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं सम्पन्न करता है और जिस ऋण-दावे के बारे में ब्याज अदा किया गया हो वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्राप्त रूप से संबंधित हो। ऐसे मामलों में अनुच्छेद 7 अथवा 14 के उपबंध यथास्थिति लागू होंगे।

7. किसी संविदाकारी राज्य में ब्याज उस स्थिति में उद्भूत होगा समझा जाएगा, जब ब्याज अदा करने वाला स्वयं वह संविदाकारी राज्य, उस संविदाकारी राज्य का कोई राजनीतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा कोई निवासी हो। किन्तु जहाँ ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं हो, किसी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान है जिसके संबंध में वह ऋण उद्भूत हुआ हो, जिन पर ब्याज को अदायोगों की गई हो और इस प्रकार का ब्याज ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है तो इन प्रकार का ब्याज उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा, जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

8. जहाँ ब्याज अदाकर्ता तथा हिस्सा स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच कोई विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण अदा की गई ब्याज को रकम, उस ऋणदावे को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए उस ब्याज को रकम अदा की गई है, उस रकम से बढ़ जाती है जिसके लिए इन प्रकार के संबंधों के तहत होने का स्थिति अदाकर्ता और हिस्सा स्वामी के बीच सहमत हो गई हो तो वहाँ इनमें अनुच्छेद के उपबंध केवल अन्तिम वर्णित राशि पर ही लागू होंगे। ऐसे मामलों में अदायोगों के अतिरिक्त भाग पर इस अभिसमय के अन्य उपबंधों का सम्यक ध्यान रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद 12

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले और दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को अदा की जाने वाली राशियों तथा तकनीकी सेवाओं के लिए फंड के भुगतान पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

को सेवाओं के लिए फीस पर

उस संविदाकारी राज्य में भी, जिसमें वे उद्भूत होता है तथा उसी संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार, कर लगाया जा सकेगा, किन्तु यदि प्राप्त-कर्ता रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभोगी स्वामी है तो इस प्रकार लगाए गए कर को राशि उक्त रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की सकल राशि के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

3. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त “रायल्टियाँ” शब्द से साहित्यिक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक कृतियों, जिनमें चलचित्र, फिल्में तथा रेडियो अथवा दूरदर्शन प्रसारण के लिए फिल्में तथा टेपें भी शामिल हैं, कोई पेटेंट ट्रेडमार्क, डिजाइन अथवा मॉडल, प्लान, गूट फार्मला अथवा प्रक्रिया के प्रयोग अथवा प्राद्योगाधिकार के लिए, कापी राइट के लिए अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपकरण अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित जानकारी के लिए उसके प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार के लिए प्राप्त किसी प्रकार की अदायगी अभिप्रेत है।

4. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त “तकनीकी सेवाओं के लिए फीस” पद से अभिप्रेत है, किसी प्रबंधकीय, तकनीकी अथवा परामर्शदात्री स्वरूप की सेवाओं के प्रतिफल में अनुच्छेद 14 में उल्लिखित स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के लिए अदायगियां करने वाले किसी व्यक्ति के किसी कर्मचारी को को जाने वाली अदायगियों से भिन्न किसी व्यक्ति को तथा किसी व्यक्ति को की गई किसी किस्म की अदायगियां।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए हितभोगी स्वामी, एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते, दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उद्भूत होती है वहां पर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां पर स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पन्न करना हो तथा जिस अधिकार, सम्पत्ति अथवा ठंके के संबंध में रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की अदायगी की जाती है, उसका संबंध प्रभावी रूप से ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से हो, ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।

6. रायल्टियों तथा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस एक संविदाकारी राज्य में उस स्थिति में उद्भूत हुई मानी जाएगी जब अदाकर्ता स्वयं वह संविदाकारी राज्य, उसका कोई राजनीतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण हो अथवा उस संविदाकारी राज्य का निवासी हो। तथापि, जहां रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के लिए भुगतान करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी एक संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा नहीं है, उस संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान, जिसके संबंध में रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा की जाती है और ऐसी रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस को ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है तो ऐसी रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के लिए भुगतान, उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा, जिसमें स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

7. जहां अदाकर्ता और हितभोगी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच, विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की रकम, रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के भुगतान का उपयोग अधिकार अथवा सूचना को ध्यान में रखते हुए, उस रकम से बढ़ जाती है जिस पर इस प्रकार का संबंध नहीं होने का दशा में अदाकर्ता और हितभोगी स्वामी सहमत हो गए होते, वहां पर इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अन्तिम

वर्णित रकम पर ही लागू होंगे। ऐसे मामले में, अधिक अदा की गई रकम इस अभिसमय के अन्य उपबंधों पर यथोचित ध्यान देते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर योग्य होंगे।

अनुच्छेद 13

1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा अनुच्छेद 6 में उल्लिखित और दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त होने वाले अभिलाभों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. अचल सम्पत्ति से भिन्न किसी ऐसे सम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त हुए अभिलाभों पर, जो दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी एक संविदाकारी राज्य के किसी स्थायी संस्थापन को व्यापारिक सम्पत्ति के भाग के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित है अथवा जो दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में उपलब्ध किसी निश्चित स्थान से संधित अचल संबंधित से भिन्न कोई सम्पत्ति हो, जिसमें ऐसे किसी स्थायी संस्थापन (अकेले अथवा सम्पूर्ण उद्यम के साथ) अथवा ऐसे निश्चित स्थान के अन्तरण से प्राप्त होने वाले अभिलाभ भी शामिल हैं, उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

3. जब तक कि पैराग्राफ 2 के उपबंध लागू नहीं हों, तब तक किसी कम्पनी, जो दूसरे संविदाकारी राज्य को निवासी हो, के शेषों के अन्तरण से एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा अर्जित अभिलाभों पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा। . . .

4. किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा अन्तर राष्ट्रीय यात्रायान में चलए जाने वाले जलयानों अथवा वायुयानों के अन्तरण से तथा ऐसे जलयानों अथवा वायुयानों के परिचालन से सम्बन्धित अचल सम्पत्ति से भिन्न किसी सम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभ पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में ही कर लगाया जाएगा।

5. किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा पैराग्राफ 1 से 4 तक में उल्लिखित सम्पत्ति से भिन्न किसी सम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में ही कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद 14

1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा व्यावसायिक सेवाओं अथवा स्वतंत्र स्वरूप वाले अन्य कार्यकलापों से प्राप्त आय तब तक उसी संविदाकारी राज्य में कराधेय होगी, जब तक उस अपने कार्यकलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध नहीं हो अथवा वह कितनी कराधेय वर्ष अथवा “पिछले वर्ष” के दौरान कुल मिलाकर 183 दिन से अधिक को अवधि या अवधियों के लिए जैसा भी मामला हो, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं रहा हो,। यदि उसके पास उस दूसरे संविदाकारी राज्य में एक ऐसा निश्चित स्थान है अथवा उक्त अवधि या अवधियों के लिए वह रहता है, तो वह आय उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कराधेय होगी परन्तु केवल उतनी ही आय कराधेय होगी, जो उक्त अवधि अथवा अवधियों के दौरान उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उस निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हुई मानी जाती है अथवा प्राप्त होती है।

2. “व्यावसायिक सेवाएं” पद के अर्थ-विस्तार में विशेषतया स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्य, कलात्मक शक्ति अथवा अध्यापन संबंध कार्यकलापों के मध्यमाध्य चिकित्साकों, शल्य चिकित्सकों, वकीलों इंजीनियरों वास्तुविदों, दन्त चिकित्साकों और लेखापालों के स्वतंत्र कार्यकलाप भी शामिल हैं।

अनुच्छेद 15

1. अनुच्छेद 16, 18, 19, 20 और 21 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतन, मजदूरी तथा इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं किया गया हो, यदि इस प्रकार का नियोजन किया जाता है तो ऐसे पारिश्रमिक पर, जो वहां से प्राप्त होता है, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा, यदि

- (क) प्राप्तकर्ता किसी करा धेय वर्ष अथवा "पूर्ववर्ती वर्ष" जैसा भी मामला हो, के दौरान कुल मिलकर 183 दिन से अधिक की अवधि अथवा अवधियों के लिए उस दूसरे संविदाकारी राज्य में मौजूदा रहा हो;
- (ख) पारिश्रमिक किसी ऐसे नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से अदा किया जाता है, जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी नहीं है, और
- (ग) पारिश्रमिक किसी ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा किसी निश्चित स्थान से वहन नहीं किया गया हो, जो नियोजन के दूसरे संविदाकारी राज्य में है।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में किसी जलयान अथवा वायुयान पर सवार होकर उसके परिचालन में किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में लगाया जा सकेगा।

अनुच्छेद 16

किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा, किसी कंपनी के निदेशक मण्डल के एक सदस्य को हैसियत में, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की एक निवासी है, प्राप्त निदेशक की फीस और अन्य समरूप अदायगियों पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगेगा।

अनुच्छेद 17

1. अनुच्छेद 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी, किसी व्यक्ति द्वारा, जो किसी संविदाकारी राज्य का निवासी है, मनोरंजनकर्ता के रूप में जैसे थियेटर, चलचित्र, रेडियो अथवा दूरदर्शन कलाकार और किसी संगीतकार या किसी खिलाड़ी के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में इस प्रकार सम्पन्न किए गए अपने व्यक्तिगत कार्यकलापों से प्राप्त आय पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा।

तथापि ऐसी आय पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी, यदि ऐसे कार्यकलाप किसी व्यक्ति द्वारा, जो प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य का निवासी है, जो संविदाकारी राज्यों की सरकारों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए स्वीकृत किसी विशेष कार्यक्रम के अनुसरण में किए जाते हैं।

2. जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा अपने उस तरह की हैसियत से किए गए व्यक्तिगत कार्यकलापों से उद्भूत आय स्वयं उस मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी को प्राप्त नहीं होकर किसी अन्य व्यक्ति को होती है, जो दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है, तो अनुच्छेद 7, 14, और 15 के उपबंधों के होते हुए भी उस आय पर कर प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में लग सकेगा।

तथापि, ऐसी आय पर उस प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त होगा यदि ऐसे कार्यकलाप दो संविदाकारी राज्यों की सरकारों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए स्वीकृत एक विशेष कार्यक्रम के अनुसरण में किए जाते हैं।

अनुच्छेद 18

अनुच्छेद 19 के पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अधीन एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को विगत में नियोजन के प्रतिफल के रूप में प्रदत्त पेंशनों और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिकों पर केवल उस संविदाकारी राज्य में लगेगा।

अनुच्छेद 19

1. (क) किसी संविदाकारी राज्य द्वारा अथवा उसके किसी राजनीतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को उस संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनीतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण के लिए सरकारी स्वरूप के किन्हीं कार्यों को सम्पन्न की गई सेवाओं के संबंध में अदा की गई पेंशन से मिल पारिश्रमिक पर कर उस संविदाकारी राज्य में ही लग सकेगा।

(ख) तथापि, ऐसे पारिश्रमिक पर केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में कर केवल उस स्थिति में लग सकेगा, यदि सेवाएं उस दूसरे संविदाकारी राज्य में की जाती हैं और वह व्यक्ति उस दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है, जो

- (i) उस दूसरे संविदाकारी राज्य का राष्ट्रिक है, अथवा
- (ii) सेवाएं सम्पन्न करने के प्रयोजनार्थ केवल उस दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी नहीं बना।

2. (क) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनीतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को उस संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनीतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण के लिए सम्पन्न की गई सेवाओं के संबंध में निधियों द्वारा अदा की गई अथवा ऐसी निधियों में से, जिसके लिए अंशदान किया जाता है, अदा की गई किसी पेंशन पर इस संविदाकारी राज्य में ही कर लग सकेगा।

(ख) तथापि ऐसी पेंशन पर केवल उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर उस स्थिति में लगेगा, यदि व्यक्ति उस दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी तथा राष्ट्रिक है।

3. अनुच्छेद 15, 16, 17 और 18 के उपबंध किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनीतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाए गए कारोबार के संबंध में सम्पन्न की गई सेवाओं के लिए प्राप्त पारिश्रमिक और पेंशनों पर लागू होंगे।

अनुच्छेद 20

किसी विद्यार्थी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षु को जो एक संविदाकारी राज्य का दौरा करने में तत्काल पूर्व दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासो है अथवा था तथा जो प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में केवल अपने अनुरक्षण, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ प्राप्त अदायगियों पर उस प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य के कर से छूट प्राप्त होगी, वशर्त कि ऐसी अदायगियां उसे उन प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य के बाहर से की जाती हैं।

अनुच्छेद 21

1. किसी प्राध्यापक अथवा अध्यापक को, जो किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय अथवा अन्य मान्यताप्राप्त अधिका संस्था में अध्यापन अथवा अनुसंधान के प्रयोजनार्थ दो वर्ष से अधिक को अवधि के लिए किसी संविदाकारी राज्य में अस्थायी रूप से दौरा करता है, तथा जो उस तरह के दौरे के तत्काल पूर्व उस दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था तो इस प्रकार के अध्यापन अथवा अनुसंधान के लिए प्राप्त पारिश्रमिक के संबंध में केवल उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा।

2. यह अनुच्छेद उस अनुसंधान कार्य से प्राप्त आय पर उस स्थिति में लागू नहीं होगा, यदि ऐसा अनुसंधान कार्य सार्वजनिक हित में नहीं किया जाता है किन्तु मूलतः वह कार्य किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों-विशेष के निजी लाभ के लिए किया जाता है।

अनुच्छेद 22

1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को आय की मदों पर, जहाँ कहीं वे उत्पन्न होती हों, इस अभिसमय के पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में जिन पर विचार नहीं किया गया हो, केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबन्ध अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में यथा-परिभाषित अचल सम्पत्ति से प्राप्त होने वाली आय से भिन्न आय पर उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि ऐसी आय को प्राप्त करने वाला किसी संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते। दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थिति किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उस संविदाकारी राज्य में व्यापार चलाता है अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में वहाँ पर वह स्थिति किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएँ निष्पन्न करता है और जिस अधिकार अथवा सम्पत्ति से प्राप्त होने वाली आय को अदायगी करता है, वह अधिकार अथवा सम्पत्ति ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित है ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा 14 के उपबन्ध जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबन्धों के होते हुए भी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की मदों पर, जिन पर इस अभिसमय के पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है, और जो दूसरे संविदाकारी राज्य में उद्भूत होती हैं दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगेगा।

अनुच्छेद 23

1. दोनों संविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त कानून अलग-अलग संविदाकारी राज्यों में आय के कराधान को नियंत्रित करते रहेंगे सिवाय उन मामलों के जहाँ पर इसके विपरीत स्पष्ट उपबन्ध इस अभिसमय में दिए गए हों।

2. भारत के मामले में दौरे कराधान का निम्न प्रकार से परिहार किया जाएगा :—

(क) जहाँ भारत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है जिस पर इस अभिसमय के उपबन्ध के अनुसार जापान में कर लगाया जा सकता है, उस स्थिति में भारत उन निवासी को उस आय पर कर से कटौती को अनुमति उत्तरी रकम के बराबर देगा जितनी रकम को अदायगी जापान में जापानी कर के लिए की गई हो, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से दिया गया हो अथवा कटौती के द्वारा दिया गया हो, किन्तु शर्तों पर जो उक्त कटौती की मात्रा अधिकतर कटौती दिए जाने से पूर्व यथा संगणित के उतने भाग में अधिक नहीं होगी, जो यथास्थिति उस आय के कारण उत्पन्न हुई हो, जिन पर जापान में कर लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जहाँ ऐसा निवासी एक कम्पनी है, जिसके माध्यम से भारत में प्रतिष्ठित देश बना हो, वहाँ जापान में या तो असा कि गये आरकर के संबंध में कटौती को अनुमति प्रथमतया उस कम्पनी द्वारा भारत में देय आय कर से देगा और जेष, रकम पर से यदि कोई हो, उसके द्वारा भारत में देय अतिरिक्त से अनुमति देगा।

(ख) जहाँ भारत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है जिस पर इस अभिसमय के उपबन्धों के अध्वधीन केवल जापान में कर लगाया जा सकता है, उस स्थिति में भारत इस आय को कर आधार में शामिल करेगा लेकिन, आरकर में से आरकर के उतने भाग को कटौती जैसा भी मामला हो, को अनुमति देगा जो जापान में उद्भूत हुई आय कारण बना हो।

3. जापानी कर को मदेनजर रखते हुए जापान से भिन्न किसी अन्य देश में देय कर पर क्रेडिट के रूप में छूट के बारे में जापान के कानूनों के अध्वधीन रहते हुए :

(क) जहाँ जापान का कोई निवासी भारत में आय प्राप्त करता है, जिस पर इस अभिसमय के उपबन्ध के अनुसार भारत में कर लगाया जा सकता है, उस स्थिति में उस आय के संबंध में देय भारतीय कर को राशि उस निवासी पर लगाए गए जापानी कर मात्रा के अनुसार क्रेडिट के रूप में, अनुमत्य होगी तथापि क्रेडिट को वह रकम जापानी कर के उस भाग से अधिक नहीं होगी, जो उस आय के लिए समुचित हो।

(ख) जहाँ भारत से प्राप्त आय किसी कंपनी द्वारा जो कि भारत की निवासी है, एक ऐसी कम्पनी को जो जापान का निवासी है, और जिसके पास लाभांश अदा करने वाली कम्पनी के वोटिंग शेयर के 25 प्रतिशत के अध्वन भाग का अथवा उस कम्पनी द्वारा जारी किए गए कुल शेयरों का स्वाभित्व है, अदा किया गया एक लाभांश हो, उस स्थिति में उस क्रेडिट को अपनी आय के संबंध में लाभांश अदा करने वाली कम्पनी द्वारा देय भारतीय कर के हिसाब में लिया जाएगा।

(ग) ऊपर उप-पैरा ग्राफों (क) और (घ) में उल्लिखित क्रेडिट के प्रयोजनार्थ करदाता द्वारा उस रकम को अदा किया गया माना जाएगा, जिसकी अदायगी भारत के कानून के अध्याधान और इस अभिसमय के अनुसार भारतीय कर के रूप में उम स्थिति में की गई होती, यदि अदा किए गए उस भारतीय कर को इस अभिसमय पर हस्ताक्षर होने की तारीख को लागू तथा भारत में आर्थिक विकास के लिए निर्मित किए गए विविध प्रोत्साहन कार्य के उपायों के अनुसार टका नहीं गया हो अथवा उनमें राहत नहीं दी गई हो अथवा जिन्हें मौजूदा उपायों के संशोधन में अथवा उनके अतिरिक्त उपायों में भारतीय कर कानूनों में भविष्य में लागू किया जा सकता हो वशते उक्त उपायों के अध्याधान करदाता को दिए गए लाभों के कार्यक्षेत्र के संबंध में दोनों सरकारों के बीच कोई वारंश सम्पन्न किया गया हो।

अनुच्छेद 24

1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रियों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसे किसी कराधान अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उस कराधान से और उन संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न अथवा भारपूर्ण हो, जो दूसरे संविदाकारी राज्य के राष्ट्रियों पर समान परिस्थितियों में लागू होती है अथवा हो सकती है। अनुच्छेद 1 के उपबंधों के होते हुए भी यह उपबंध ऐसे व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी एक संविदाकारी राज्य के अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी नहीं है।

2. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन पर लगाया जाने वाला कर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उस कर से अपेक्षाकृत कम अनुकूल नहीं होगा, जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य में समान कार्य कलापों में लगे हुए उद्यमों पर लगाया जाता है।

इस उपबंध में निहित किसी भी बात का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि एक संविदाकारी राज्य ऐसे व्यक्तियों को, जो दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी है, नागरिक हेमियत अथवा पारिवारिक उत्तरदायित्वों के कारण कराधान के प्रयोजनों के लिए किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत छूटें, राहतें और घटौतियां प्रदान करने को बाध्य होगा, जो वह अपने स्वयं के निवासियों को प्रदान करता है।

3. अनुच्छेद 9 के उपबंध, अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 8 अथवा अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 7 के उपबंध जहां लागू होते हैं उनको छोड़कर एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को ऐसे उद्यम के कारखेय लाभों का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ अदा किए गए व्याज, रायल्टियों तथा अन्य भुगतानों को उन समान परिस्थितियों के तहत कटौती योग्य माना जाएगा, यदि उनकी अदायगी प्रथमोल्लिखित संविदाकार राज्य के किसी निवासी को की गई हो।

4. एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर जिनकी पूंजी पूर्णतः अथवा अंशतः दूसरे संविदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक निवासियों के प्रत्यक्षतः अथवा अल्पप्रत्यक्षतः स्वामित्व अथवा नियंत्रण में है, प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में कोई ऐसा कराधान अथवा तत्संबंधी कोई ऐसी अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उस कराधान और तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो, जो उस प्रथमोल्लिखित राज्य के अन्य इसी तरह के उद्यमों पर लागू होती है अथवा हो सकती है।

5. इस अनुच्छेद में "कराधान" शब्द से तात्पर्य उन करों से है जो इस अभिसमय के विषय हैं।

अनुच्छेद 25

1. जहां कोई व्यक्ति यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों के कार्यों के परिणामस्वरूप उस पर कर लगा है अथवा लगाया जाएगा, जो इस अभिसमय के उपबंधों के अनुकूल नहीं है, तो वह उन संविदाकारी राज्यों के घरेलू नियमों द्वारा उपबंधित उपचारी उपायों के होते हुए भी अपना मामला उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रख सकता है जिसका वह निवासी है अथवा यदि उसका मामला अनुच्छेद 24 के पैराग्राफ 1 के अंतर्गत आता है, तो वह अपना मामला उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है जिसका वह राष्ट्रिक है। यह मामला उस कार्य की प्रथम अधिमूर्चना के तीन वर्षों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसके कारण इस अभिसमय के उपबंधों के अनुरूप कर नहीं लगा है।

2. यदि सक्षम प्राधिकारों का अपेक्षा उचित जगह और यदि वह स्वयं किसी संतोषजनक हल पर पहुंचने में असमर्थ हो तो वह ऐसे कराधान के निवारण की दृष्टि से, जो इस अभिसमय के उपबंधों के अनुरूप नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी की परस्पर सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा। प्राप्त हुए किसी भी समझौते को किसी तरह की समय सीमा पर ध्यान न देने हुए संविदाकारी राज्यों के घरेलू कानूनों के तहत, कार्यान्वित किया जाएगा।

3. इस अभिसमय की व्याख्या करने अथवा इसे लागू करने में यदि कोई वादग्रस्त अथवा शंकाएं उत्पन्न हों, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे। वे उन मामलों में दोहरे कराधान के अपाकरण के लिए परस्पर विचार-विमर्श कर सकते हैं, जिनकी व्यवस्था इस अभिसमय में नहीं की गई है।

4. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती पैराग्राफों में व्यक्ति अभिप्राय को लेकर सहमति के प्रयोजनार्थ एक दूसरे के साथ प्रत्यक्षतः पत्र-व्यवहार कर सकते हैं।

अनुच्छेद 26

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारों ऐसी सूचना का आदान-प्रदान करेंगे जो इस अभिसमय के उपबंधों के अंतर्गत आने वाले करों से संबंधित, जहां तक उसके अंतर्गत कराधान इस अभिसमय के उपबंधों के प्रतिकूल नहीं है, इस अभिसमय के अथवा संविदाकारी राज्यों के घरेलू कानूनों के उपबंधों को कार्यान्वित करने अथवा राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए अथवा ऐसे करों की जालसाजी को रोकने के लिए आवश्यक है। इस तरह से आदान-प्रदान की गई किसी भी सूचना को गोपनीय समझा जाएगा और इसे इस अभिसमय में समाविष्ट करों के निर्धारण अथवा उनकी वसूली अथवा उनको लागू करने अथवा उनके बारे में अभियोजन संबंधी कार्रवाही करने में अथवा उनसे संबंधित अपीलों का निर्धारण करने में लगे हुए व्यक्तियों अथवा प्राधिकरणों जिनमें न्यायालय भी शामिल हैं, को ही प्रकट किया जाएगा।

2. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 के उपबंधों का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा, जिसमें कि किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डाला जाए :

(क) एक अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों और प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना ;

(ख) ऐसी सूचना देना जो एक अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्ति नहीं है, अथवा

(ग) ऐसी सूचना देना जिससे कोई व्यापारिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यवसाय संबंधी गुप्त भेद अथवा व्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती है, जिसको प्रकट करना सरकारी नीति के प्रतिकूल हो।

अनुच्छेद 27

अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सामान्य नियमों के अन्तर्गत अथवा विशेष करारों के प्रावधानों के अन्तर्गत इस अभिसमय के कारण राजनयिक अधिकारियों अथवा कौमुदी अधिकारियों के वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुच्छेद 28

1. इस अभिसमय को यथापूर्व शीघ्र टोकियो में अनुसमर्थित किया जाएगा और अनुसमर्थन के दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया जाएगा।

2. यह अभिसमय अनुसमर्थन के दस्तावेजों के आदान-प्रदान की तारीख के पश्चात् 30वें दिन को लागू होगा और इसका निम्नानुसार प्रभाव होगा :

(क) जापान में :

जिस कैलेण्डर वर्ष में यह अभिसमय प्रवर्तित होता है उसके पश्चात् वर्ष के जनवरी मास के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी कारागार वर्ष के लिए प्राप्त आय के संबंध में ; और

(ख) भारत में :

जिस कैलेण्डर वर्ष में यह अभिसमय प्रवर्तित होता है उसके पश्चात् वर्ष के अप्रैल मास के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात् प्रारम्भ होने वाले किसी भी "पूर्ववर्ती वर्ष" के लिए प्राप्त आय के संबंध में।

3. आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के निवारण के लिए दिनांक 5 जनवरी, 1960 को नई दिल्ली में जापान और भारत के बीच हस्ताक्षरित हुआ करार इस आय के संबंध में समाप्त होने के साथ-साथ निष्प्रभावी भी हो जाएगा, जिसके बारे में यह अभिसमय पैराग्राफ 3 के उपबंधों अध्वनीत लागू होता है।

अनुच्छेद 29

यह अभिसमय अनिश्चित काल तक लागू रहेगा लेकिन दोनों संविदाकारी राज्यों में से कोई भी संविदाकारी राज्य इसके लागू होने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् आरंभ होने वाले किसी भी कैलेण्डर वर्ष के जून मास के 30वें दिन को अथवा उससे पहले राजनयिक माध्यमों से दूसरे संविदाकारी राज्य को इसकी समाप्ति का लिखित रूप में नोटिस दे सकेगा और ऐसी स्थिति में यह अभिसमय निम्नलिखित के लिए निष्प्रभावी हो जाएगा :

(क) जापान में :

जिस कैलेण्डर वर्ष में अभिसमय की समाप्ति के बारे में नोटिस दिया जाता है उसके पूर्ववर्ती वर्ष के जनवरी के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात् शुरू होने वाले किसी भी कारागार वर्ष के लिए प्राप्त आय के संबंध में ; और

(ख) भारत में :

जिस कैलेण्डर वर्ष में अभिसमय की समाप्ति के बारे में नोटिस दिया जाता है उसके पश्चात् वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात् शुरू होने वाले किसी भी "पूर्ववर्ती वर्ष" के लिए प्राप्त आय के संबंध में।

जिसके माध्यम से इसके लिए अग्नी-प्रपत्ति सरकारों द्वारा विधिवत प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरकर्तृओं ने इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं।

यह एक हजार नौ सौ नवामी के मार्च माह के सातवें दिन को नई दिल्ली में हिन्दी, जापानी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतिकों में लिप्यक्ष किया गया, जिसके तीनों पाठ समानतः प्रामाणिक हैं। अर्थनिरूपण में किसी प्रकार की भिन्नता के मामले में अंग्रेजी पाठ ही प्रभावी होगा।

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से

जापान की सरकार
की ओर से

(इजिटो तोडा)

नई दिल्ली, 7 मार्च, 1989

मान्यवर,

भारत गणराज्य की सरकार और जापान सरकार के बीच आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अवबंचन को रोकने के लिए हुए इस अभिसमय, जिस पर आज हस्ताक्षर किए गए हैं के अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (ग) का हवाला देने और भारत गणराज्य की सरकार की ओर से भारत गणराज्य की सरकार और जापान की सरकार के बीच हुए निम्नलिखित समझौते की पुष्टि करने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ है :—

भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की निम्नलिखित धाराओं में विनिर्दिष्ट उपाय, जिनका उल्लेख उक्त पैराग्राफ में किया गया है, वे हैं : "भारत में आर्थिक विकास की उन्नति के लिए अभिलक्षित विशेष प्रोत्साहनकारी उपाय जो इस अभिसमय पर हस्ताक्षर होने की तारीख से प्रभावी होंगे।"

(i) धारा 10 (15)(IV)

—जो कतिपय व्याज पर कर से छूट से संबंधित है

(ii) धारा 10क

--जो मुक्त व्यापार क्षेत्रों में स्थापित नए औद्योगिक उपक्रमों की बाबत विशेष उपबंध से संबंधित है ;

(iii) धारा 32कख

--जो संयंत्र तथा मशीनरी आदि में निवेश के संबंध में विनिधान निक्षेप खाने से संबंधित है ;

(iv) धारा 80अ

--जो पिछड़े क्षेत्रों में नए स्थापित औद्योगिक उपक्रमों या होटल कारोबार से प्राप्त लाभों और अभिलाभों की बाबत कटौती से संबंधित है ;

(v) धारा 80अ

--जो किसी निश्चित तारीख के पश्चात् औद्योगिक उपक्रमों से लाभों और अभिलाभों की बाबत कटौती आदि से संबंधित है ;

मुझे जापान की सरकार की ओर से पूर्वोक्त बातों को पूर्ण पुष्टि करने के लिए आपके महामहिम से अनुरोध करने का भी गौरव प्राप्त हुआ है

मैं आपके महामहिम को अपने उच्चतम दृष्टिकोण का आश्वासन देने के लिए इस अवसर का लाभ उठाता हूँ।

(ह०/-)

जो. एन. गुप्ता

अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

वित्त मंत्रालय

महामहिम श्री एड्जोरो नोडा

भारत में जापान के असाधारण

एवं पूर्वाधिकारी राजदूत

नई दिल्ली, 7 मार्च, 1989

मान्यवर,

मुझे आज की तारीख के आपके महामहिम की टिप्पणी को पावती देने का गौरव प्राप्त हुआ है जो निम्न प्रकार से पठनीय है:--

“भारत गणराज्य की सरकार और जापान सरकार के बीच आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए हुए उस अभिसमय जिस पर आज हस्ताक्षर किए गए हैं, के

अनुच्छेद 23 के पैराग्राफ 3 के उप-पैराग्राफ (ग) का हवाला देने और भारत गणराज्य की सरकार की ओर से भारत गणराज्य की सरकार और जापान की सरकार के बीच हुए निम्नलिखित समझौते को पुष्टि करने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ है :-

भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) का निम्नलिखित धाराओं में अतिरिष्ट उपाय, जिनका उल्लेख उक्त पैराग्राफ में किया गया है, ये हैं: “भारत में अधिक विकास को उत्पत्ति के लिए अभिकल्पित विशेष प्रोत्साहककारी उपाय जो इस अभिसमय पर हस्ताक्षर होने को तारीख से प्रभावी होंगे।”

(i) धारा 10(15)(iv)

--जो कॉपीय व्यापार पर कर में छूट से संबंधित है ;

(ii) धारा 10क

--जो मुक्त व्यापार-क्षेत्रों में स्थापित नए औद्योगिक उपक्रमों की बाबत विशेष उपबंध से संबंधित है ;

(iii) धारा 32कख

--जो संयंत्र तथा मशीनरी आदि में निवेश के पश्चात् में विनिधान निक्षेप खाने आदि से संबंधित है ;

(iv) धारा 80अ

--जो पिछड़े क्षेत्रों में नए स्थापित औद्योगिक उपक्रमों या होटल कारोबार से प्राप्त लाभों की बाबत कटौती से संबंधित है ;

(v) 80अ

--जो किसी निश्चित तारीख के पश्चात् औद्योगिक उपक्रमों से लाभों और अभिलाभों की बाबत कटौती आदि से संबंधित है ;

मुझे जापान की सरकार की ओर से पूर्वोक्त समझौते का महर्ष पुष्टि करने के लिए आपके महामहिम से अनुरोध करने का भी गौरव प्राप्त हुआ है।”

इसके अतिरिक्त, जापान सरकार की ओर से आपके महामहिम की टिप्पणी में अतिरिष्ट समझौते का पुष्टि करने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ है।

मैं आपके महामहिम को अपने उच्चतम दृष्टिकोण का आश्वासन देने के लिए इस अवसर का लाभ उठाता हूँ।

(ह०/-)

एड्जोरो नोडा

भारत में जापान के असाधारण एवं पूर्वाधिकारी राजदूत

महामहिम श्री जो. एन. गुप्ता

अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

वित्त मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 मार्च, 1989

मान्यवर,

मुझे जापान सरकार और भारत गणराज्य को सरकार के बीच आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपव्यय को रोकने के लिए सम्पन्न हुए अभिसमय का हवाला देने, जिस पर आज हस्ताक्षर हुए हैं और जापान सरकार को और सदोनों सरकारों के बीच हुए निम्नलिखित समझौते की पुष्टि करने का मौखिक प्राप्ति हुआ है।

1. इस अभिसमय के अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (ख) के संदर्भ में किन्हीं भी करों को, जो कंपनो (लाभ) अधिकार अधिनियम, 1964 के अंतर्गत लगाए गए अधिकारों के समान हैं अथवा सारतः उसी प्रकार के हैं लेकिन बाद में जिन्हें समप्त कर दिया गया और जिन्हें इस अभिसमय के हस्ताक्षर होने की तारीख के पश्चात् भारत में लागू किया गया है, इस अभिसमय के अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 2 में उल्लिखित परों के समान अथवा सारतः उसी प्रकार के कर समझा जाएगा।

2. इस अभिसमय के अनुच्छेद 3 के पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (घ) के संदर्भ में "कर" शब्द में ऐसी कोई रकम शामिल नहीं होगी जो उन करों के संबंध में किसी भूल अथवा चूक के संबंध में देय है जिसके लिए यह अभिसमय लागू होता है अथवा जो इन करों के संबंध में लगाये गये किसी दंड को दर्शाता है।

3. इस अभिसमय के अनुच्छेद 3 के पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (ङ) के संदर्भ में भारत के मामले में "अकि" पद में कोई भागीदारिता और कोई हिन्दू अविभाजित परिवार भी शामिल होगा।

4. इस अभिसमय के अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 5 के संदर्भ में उसमें उल्लिखित "सेवाएं अथवा सुविधाएं" शब्दों में खनिज तेलों की खोज करने, समुपयोजन करने अथवा उनके निष्कर्षण में प्रयुक्त किए गए अथवा प्रयुक्त किए जाने के लिए किराए पर लिए जाने वाले मंत्रों तथा मशीनों को आपूर्ति भी शामिल होगी।

5. ऐसा समझा जाता है कि इस अभिसमय के अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 6 के उपबंध, किसी उद्यम के माल अथवा पण्य वस्तुओं की डिलीवरी मात्र के प्रयोजन के लिए सुविधाओं के उपयोग के लिए अथवा डिलीवरी मात्र के प्रयोजन के लिए उद्यम के माल अथवा पण्य वस्तुओं के उस स्टॉक के रख-रखाव हेतु लागू होंगे जब तक कि ऐसे माल अथवा पण्य वस्तुओं को बिक्री उस दूसरे संवेदाकारी राज्य में होती है।

6. इस अभिसमय के अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 1 के संदर्भ में यह समझा जाता है कि उस "स्थायी संस्थापन के कारण प्रत्यक्षः अथवा अप्रत्यक्षः" पद का प्रयोग करते हुए माल के लेन-देन के सौदों से उद्भूत उन अभिलाषों को

जिनमें स्थायी संस्थापन अंतर्भूत है, स्थायी संस्थापन के कारण उस स्थायी सीमा तक उद्भूत हुआ समझा जाएगा जो लेन-देन के उन सौदों में स्थायी संस्थापन द्वारा किए गए कार्यों के लिए समुचित होगा। यह भी समझा जाता है कि अभिलाषों को अगर उल्लिखित माल तक स्थायी संस्थापन के कारण उत्पन्न हुआ समझा जाएगा, भले ही प्रत्यक्ष माल को बिक्री अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित संवेदा अथवा आर्डर स्थायी संस्थापन को बनाए उस उद्यम के समुद्रपार स्थित प्रधान कार्यालय के सामने किया जाता है अथवा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।

7. इस अभिसमय के अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 के संदर्भ में यह समझा जाता है कि भारत में उक्त पैराग्राफ में यथा उल्लिखित कार्यकारी और सामान्य प्रशासनिक खर्चों के संबंध में कटौतियां भारत के आंतरिक कानूनों के अनुसार, अनुसृत्य होंगी लेकिन ऐसे कटौतियों का मात्रा किसी भी दशा में इस अभिसमय के हस्ताक्षर की तारीख से लागू भारतीय आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अनुसृत्य रकम से कम नहीं होगी।

8. इस अभिसमय के अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 के संदर्भ में किसी उद्यम के किसी स्थायी संस्थापन द्वारा उस उद्यम के प्रधान कार्यालय को अथवा उसके किन्हीं अन्य कार्यालयों को निम्नलिखित के रूप में प्रदत्त राशियों अथवा प्रसारित राशियों (वारनविक खर्चों को प्रतिपूर्ति से भिन्न) के संबंध में कोई कटौती नहीं दी जाएगी:

(क) पेटेंट अथवा अन्य अधिकारों के इस्तेमाल के लिए अथवा जानकारों के इस्तेमाल के लिए आय विवरणों में रायल्टियों, फीसों अथवा इसी प्रकार के अन्य भुगतान,

(ख) निष्पादित विनिष्ट सेवाओं अथवा प्रबंध व्यवस्था के लिए कमीशन अथवा अन्य प्रसार, और

(ग) स्थायी संस्थापन को उधार दी गई रकमों पर ब्याज, सिवाय उस मामले में जहां वह उद्यम, कोई बैंकिंग संस्था है।

9. इस अभिसमय के अनुच्छेद 8 के संदर्भ में,

(i) अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के संचालन के संबंध में अस्थायी रूप से नियोजित निधियों पर ब्याज को ऐसे जलयानों अथवा वायुयानों के संचालन से प्राप्त आय के रूप में समझा जाएगा और ऐसे ब्याज के संबंध में अनुच्छेद 11 के उपबंध लागू नहीं होंगे, और

(ii) जलयानों अथवा वायुयानों के संचालन से प्राप्त हुई आय में, अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में माल अथवा पण्य वस्तुओं के परिवहन के संबंध में कंटेनरों (जिनमें कंटेनरों के परिवहन के लिए ट्रेलर्स तथा उनसे संबंधित उपकरण भी शामिल हैं) के इस्तेमाल, रख-रखाव अथवा किराए से प्राप्त आय भी शामिल है

10. इस अभिसमय के अनुच्छेद 8 के पैराग्राफ 5 के संदर्भ में, यदि भारत का कोई स्थायी प्राधिकरण, इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख के बाद जापान में उद्यम करके पर्याप्त रूप से समान-स्वरूप के कोई कर लगाता है तो दोनों सरकारें एक-दूसरे के आधार पर ऐसी रीति से, जैसा कि वे उचित समझती हों, अनुच्छेद 8 के पैराग्राफ 5 का संशोधन करने के लिए परामर्श करेंगी।

मुझे आपके महामहिम की सरकार की ओर से पूर्वोक्त समझौते का सहर्ष पुष्टि करने के लिए आपके महामहिम से अनुरोध करने का भी गौरव प्राप्त हुआ है।

मैं आपके महामहिम की अपने उच्चतम दृष्टिकोण के आशयान का पुनः स्मरण कराने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना है।

ह

एड्जोडो नोडा,

भारत में जापान के असाधारण एवं पूर्णाधिकारी राजदूत

महामहिम श्री जी.एन. गुप्ता,

अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 मार्च, 1989

मार्च, 7

मुझे आज की तारीख के आपके महामहिम की टिप्पणी का पावती स्वीकारने का गौरव प्राप्त हुआ है जो निम्न प्रकार से पढ़ी जाएगी :

“मुझे जापान सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपव्यय को रोकने के लिए सम्पन्न हुए उस अभिसमय का हवाला देने, जिस पर आज हस्ताक्षर हुए हैं और जापान सरकार की ओर से दोनों सरकारों के बीच हुए निम्नलिखित समझौते का पुष्टि करने का गौरव प्राप्त हुआ है।

1. इस अभिसमय के अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (ख) के संदर्भ में किन्हीं भी करों की, जो कर्पा (लाभ) अधिकार अधिनियम 1964 के अंतर्गत लगाए गए अधिकारों के समान हैं अथवा समान रसी प्रकार के हैं लेकिन बाद में जिन्हें समाप्त कर दिया गया और जिन्हें इस अभिसमय के हस्ताक्षर होने की तारीख के पश्चात् भारत में लागू किया गया है, इस अभिसमय के अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 2 में उल्लिखित करों के समान प्रवेश भारत : उां प्रकार के कर समझा जाएगा।

2. इस अभिसमय के अनुच्छेद 3 के पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (घ) के संदर्भ में “कर” शब्द में ऐसी कोई रकम शामिल नहीं होगी जो उन करों के संबंध में किन्हीं भूल अथवा चूक के संबंध में देय है। जिसके लिए यह अभिसमय लागू होता है अथवा जो इन करों के संबंध में लगाये गये किन्हीं दंड का दर्शना है।

3. इस अभिसमय के अनुच्छेद 3 के पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (ङ) के संदर्भ में, भारत के मामले में “व्यक्ति” पद में कोई भागीदारिता और कोई हिन्दू अविभाजित परिवार भी शामिल होगा।

4. इस अभिसमय के अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 5 के संदर्भ में उसमें उल्लिखित “सेवाएँ अथवा सुविधाएँ” शब्दों में खनिज तेलों का खोज करने, समुपयोजन करने अथवा उनके निष्कर्षण में प्रयुक्त किए गए अथवा प्रयुक्त किए जाने के लिए किराए पर लिए जाने वाले संयंत्र तथा मशीनरी को आपूर्ति भी शामिल होगी।

5. ऐसा समझा जाता है कि इस अभिसमय के अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 6 के उपबंध किन्हीं उद्यम के माल अथवा पण्य वस्तुओं की डिलीवरी मात्र के प्रयोजन के लिए सुविधाओं के उपयोग अ लिए अथवा डिलीवरी मात्र के प्रयोजन के लिए उद्यम के माल अथवा पण्य वस्तुओं के उस स्टॉक के रख-रखाव हेतु लागू होंगे जब तक कि ऐसे माल अथवा पण्य वस्तुओं की बिक्री उस दूसरे संबिदाकारी राज्य में होती है।

6. इस अभिसमय के अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 1 के संदर्भ में यह समझा जाता है कि उस “स्थायी संस्थापन के कारण प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः” पद का प्रयोग करते हुए माल के लेन-देन के संदिग्ध से उद्भूत उन अभिलाषों को जिनमें स्थायी संस्थापन अंतर्गर्त है, स्थायी संस्थापन के कारण उस सीमा तक उद्भूत हुआ समझा जाएगा जो लेन-देन के उन संदिग्ध में स्थायी संस्थापन द्वारा किए गए कार्यों के लिए समुचित होगा यह भी समझा जाता है कि अभिलाषों की ऊपर उल्लिखित सीमा तक स्थायी संस्थापन के कारण उत्पन्न हुआ समझा जाएगा, भले ही प्रश्नगत माल की बिक्री अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित संबिदा अथवा आर्डर स्थायी संस्थापन की बजाए उस उद्यम के समुद्रपार स्थित प्रधान कार्यालय के सामने किया जाता है अथवा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।

7. इस अभिसमय के अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 के संदर्भ में यह समझा जाता है कि भारत में उक्त पैराग्राफ में यथा-उल्लिखित कार्यकारी और सामान्य प्रशासनिक खर्चों के संबंध में कटौतियाँ भारत के आन्तरिक कानूनों के अनुसार अनुमत्य होंगी लेकिन ऐसी कटौतियों की मात्रा किसी भी दशा में इस अभिसमय के हस्ताक्षर की तारीख से लागू भारतीय आयकर अधिनियम के अंतर्गत अनुमत्य रकम से कम नहीं होगी।

8. इस अधिसूचना के अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 के संदर्भ में किसी उद्यम के किसी स्थायी संस्थापन द्वारा उस उद्यम के प्रधान कार्यालय को अथवा उसके किसी अन्य कार्यालयों को निम्नलिखित के रूप में प्रदत्त राशियाँ अथवा प्रसारित राशियाँ (वास्तविक खर्चों की प्रतिपूर्ति से भिन्न) के संबंध में कोई कटौती नहीं दी जाएगी :

(क) पेटेंट अथवा अन्य अधिकारों के इस्तेमाल के लिए अथवा जानकारी के इस्तेमाल के लिए आय दिव्यरणा में राशियाँ, फीसों अथवा इसी प्रकार के अन्य भुगतान ,

(ख) निष्पादित दिशष्ट सेवाओं अथवा प्रबंध-व्यवस्था के लिए कमीशन अथवा अन्य प्रसार , और

(ग) स्थायी संस्थापन को उधार दी गई रकमों पर व्याज , सिवाय उस मामले में जहाँ वह उद्यम कोई बैंकिंग संस्था है ।

9. इस अधिसूचना के अनुच्छेद 8 के सद्वर्णन में,

(i) अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के संचालन के संबंध में अस्थायी रूप से निक्षेपित निधियों पर व्याज को ऐसे जलयानों अथवा वायुयानों के संचालन से प्राप्त आय के रूप में समझा जाएगा और ऐसे व्याज के संबंध में अनुच्छेद 11 के उपबर्ध लागू नहीं होंगे , और

(ii) जलयानों अथवा वायुयानों के संचालन से प्राप्त हुई आय में, अन्तरराष्ट्रीय यातायात में नाल अथवा अन्य वस्तुओं के परिवहन के संबंध में कंटेनरों (जिसमें कंटेनरों के परिवहन के लिए ट्रेलर्स तथा उनसे संबंधित उपकरण भी शामिल हैं) के इस्तेमाल, रख-रखाव अथवा किराए से प्राप्त आय भी शामिल है ।

10. इस अधिसूचना के अनुच्छेद 8 के पैराग्राफ 5 के संदर्भ में, यदि भारत का कोई स्थानीय प्राधिकरण, इस अधिसूचना पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख के बाद जापान में उद्यम-कर के पर्याप्त रूप से समान-स्वरूप के कोई कर लगाता है तो दोनों सरकारें एक-दूसरे के आधार पर ऐसी रीति से, जैसा कि वे उचित समझती हों, अनुच्छेद 8 के पैराग्राफ 5 का संशोधन करने के लिए परामर्श करेंगी ।

मुझे आपके महामहिम की सरकार की ओर से पूर्वोक्त समझने की सहर्ष पुष्टि करने के लिए आपके महामहिम से अनुरोध करने का भी गौरव प्राप्त हुआ है ।'

इसके अतिरिक्त, भारत गणराज्य की सरकार की ओर से आपके महामहिम की टिप्पणी में अन्तर्दिष्ट समझने की पुष्टि करने का भी मुझे गौरव प्राप्त हुआ है ।

मैं आपके महामहिम को अपने उच्चतम दृष्टिकोण के आश्वासन का पुनः स्मरण कराने के लिए इस अवसर का लाभ उठाता हूँ ।

ह.

जी. एन. गुप्ता

अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
धन मंत्रालय

महामहिम श्री एड्जीरो नोडा, भारत में जापान के असाधारण एवं पूर्णधिकारी राजदूत

[अधिसूचना नं. 8587/फा. गं.-506/69/81-एफ टी डी]

पं. के. अण्णाचु, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Foreign Tax Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 1990

INCOME-TAX

G.S.R. 101(E).—Whereas the annexed Convention between the Government of the Republic of India and the Government of Japan for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income has come into force on the 29th December, 1989 after the exchange of Instruments of Ratification as required by paragraph 1 of Article 28 of the said Convention;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Convention shall be given effect to in the Union of India.

ANNEXURE

CONVENTION

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF JAPAN FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Government of the Republic of India and the Government of Japan,

Desiring to conclude a new Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income.

Have agreed as follows :

Article 1

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

1. The taxes which are the subject of this Convention are :

(a) In Japan :

(i) the income tax; and

(ii) the corporation tax (hereinafter referred to as "Japanese tax");

(b) In India:

the income-tax including any surcharge thereon (hereinafter referred to as "Indian tax").

2. This Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of this Convention in addition to, or in place of, those referred to in paragraph 1. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which have been made in their respective taxation laws within a reasonable period of time after such change.

Article 3

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires :

(a) the term "Japan", when used in a geographical sense, means all the territory of Japan, including its territorial sea, in which the laws relating to Japanese tax are in force, and all the area beyond its territorial sea, including the seabed and subsoil thereof, over which Japan has jurisdiction in accordance with international law and in which the laws relating to Japanese tax are in force;

(b) the term "India" means the territory of India including the territorial sea and any other maritime zone in which India has sovereign rights according to the Indian law and in accordance with international law;

(c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Japan or India, as the context requires;

(d) the term "tax" means Japanese tax or Indian tax, as the context requires;

(e) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;

(f) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

(g) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean

respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

(h) the term "nationals" means :

(i) in respect of Japan :

all individuals possessing the nationality of Japan and all juridical persons created or organized under the laws of Japan and all organizations without juridical personality treated for the purposes of Japanese tax as juridical persons created or organized under the laws of Japan ;

(ii) in respect of India :

(aa) all individuals possessing the nationality of India;

(bb) all legal persons, partnerships and associations deriving their status as such from the laws in force in India;

(i) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State; and

(j) the term "competent authority" means :

(i) in Japan, the Minister of Finance or his authorized representative;

(ii) in India, the Central Government in the Ministry of Finance, Department of Revenue, or their authorized representative.

2. As regards the application of this Convention by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that Contracting State concerning the taxes to which this Convention applies.

Article 4

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that Contracting State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of head or main office or any other criterion of a similar nature.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person is a resident of both Contracting States, then the competent authorities of the Contracting States shall determine by mutual agreement the Contracting State of which that person shall be deemed to be a resident for the purposes of this Convention.

Article 5

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" includes especially:

- (a) a place of management;
- (b) a branch;
- (c) an office;
- (d) a factory;
- (e) a workshop;
- (f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources;
- (g) a warehouse in relation to a person providing storage facilities for others;
- (h) a farm, plantation or other place where agriculture, forestry, plantation or related activities are carried on;
- (i) a store or other sales outlet; and
- (j) an installation or structure used for the exploration of natural resources, but only if so used for a period of more than six months.

3. A building site or construction, installation or assembly project constitutes a permanent establishment only if it lasts more than six months.

4. An enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State and to carry on business through that permanent establishment if it carries on supervisory activities in that Contracting State for more than six months in connection with a building site or construction, installation or assembly project which is being undertaken in that Contracting State.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 3 and 4 an enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State and to carry on business through that permanent establishment if it provides services or facilities in that Contracting State for more than six months in connection with the exploration, exploitation or extraction of mineral oils in that Contracting State.

6. Notwithstanding the provisions of the preceding paragraphs of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include :

- (a) use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;
- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display ;
- (c) the maintenance for a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;
- (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, pay other activity of a preparatory or auxiliary character.

7. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person other than an agent of an independent status to whom paragraph 8 applies—is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned Contracting State, if

- (a) he has and habitually exercises in that Contracting State an authority to conclude contracts on behalf of the enterprise, unless his activities are limited to those mentioned in paragraph 6 which, if exercised through a fixed place of business, would

not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph;

- (b) he has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned Contracting State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise; or

- (c) he habitually secures orders in the first-mentioned Contracting State, wholly or almost wholly for the enterprise itself or for the enterprise and other enterprise controlling, controlled by, or subject to the same common control as that enterprise.

8. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that Contracting State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.

9. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other Contracting State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other

Article 6

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property situated in the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the laws of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting immovable property apply, usufruct of immovable property and rights to variable, or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources, ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in that other Contracting State but only so much of them as is directly or indirectly attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are

incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the Contracting State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the provisions of the preceding paragraphs of this Article, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Article of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

1. Profits from the operation of aircraft in international traffic carried on by an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State.

2. Profits from the operation of ships in international traffic carried on by an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, such profits may be taxed in the other Contracting State from which they are derived during a period of first ten taxable years or "previous years", as the case may be, for which this Convention shall have effect provided that the tax so charged shall not exceed :—

(a) during the first five years, 50 per cent,

(b) during the remaining five years, 25 per cent, of the tax otherwise imposed by the taxation law of that other Contracting State.

4. The provisions of the preceding paragraphs of this Article shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

5. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, also apply to the enterprise tax in Japan and to any tax similar to the said enterprise tax if and when such a tax is imposed in India.

Article 9

1. Where :

(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but

for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that Contracting State—and taxes accordingly—profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other Contracting State and where the competent authorities of the Contracting States agree upon consultation, that all or part of the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned Contracting State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other Contracting State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those agreed profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention.

Article 10

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, and according to the laws of that Contracting State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the dividends.

The provisions of this paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt instruments, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the taxation laws of the Contracting State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other Contracting State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other Contracting State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other Contracting State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other Contracting State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in that other Contracting State.

Article 11

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the laws

of that Contracting State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed :

- (a) 10 per cent of the gross amount of the interest if the beneficial owner is a bank; and
- (b) 15 per cent of the gross amount of the interest in all other cases.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State and derived by the Government of the other Contracting State, a political sub-division or a local authority thereof, the Central Bank of that other Contracting State or any financial institution wholly owned by that Government, or by any resident of the other Contracting State with respect to debt-claims guaranteed or indirectly financed by the Government of that other Contracting State, a political sub-division or a local authority thereof, the Central Bank of that other Contracting State or any financial institution wholly owned by that Government shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State.

4. For the purposes of paragraph 3, the terms "the Central Bank" and "financial institution wholly owned by the Government" mean :

- (a) the case of Japan :
 - (i) the Bank of Japan;
 - (ii) the Export-Import Bank of Japan;
 - (iii) the Overseas Economic Cooperation Fund;
 - (iv) the Japan International Cooperation Agency; and
 - (v) such other financial institution the capital of which is wholly owned by the Government of Japan as may be agreed upon from time to time between the Government of the two Contracting States;
- (b) in the case of India :
 - (i) Reserve Bank of India;
 - (ii) Export-Import Bank of India;
 - (iii) such other financial institution the capital of which is wholly owned by the Government of India as may be agreed upon from time to time between the Government of the two Contracting States.

5. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from Government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prize attaching to such securities, bonds or debentures.

6. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other Contracting State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

7. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political sub-division or a local authority thereof or a resident of that Contracting State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with

which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

8. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only or to the last mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 12

1. Royalties and fees for technical services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. However, such royalties and fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that Contracting State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties or fees for technical services, the tax so charged shall not exceed 20 per cent of the gross amount of the royalties or fees for technical services.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films and films or tapes for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The term "fees for technical services" as used in this Article means payments of any amount to any person other than payments to an employee of a person making payments and to any individual for independent personal services referred to in Article 14, in consideration for the services of a managerial, technical or consultancy nature, including the provisions of services of technical or other personnel.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties or fees for technical services, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties or fees for technical services arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other Contracting State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right, property or contract in respect of which the royalties or fees for technical services are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

6. Royalties and fees for technical services shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political sub-division, a local authority thereof or a resident of that Contracting State. Where, however, the person paying the royalties or fees for technical services, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties or fees for technical services was incurred, and such royalties or fees for technical services are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties or fees

for technical services, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payment shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. Gains from the alienation of any property, other than immovable property, forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of any property, other than immovable property, pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or together with the whole enterprise) or of such a fixed base, may be taxed in that other Contracting State.

3. Unless the provisions of paragraph 2 are applicable gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

4. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic and any property, other than immovable property, pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in that Contracting State.

5. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1 to 4, shall be taxable only in that Contracting State.

Article 14

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that Contracting State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities or he is present in that other Contracting State for a period or periods exceeding in the aggregate 183 days during any taxable year or "previous year", as the case may be. If he has such a fixed base or remains in that other Contracting State for the aforesaid period or periods, the income may be taxed in that other Contracting State but only so much of it as is attributable to that fixed base or is derived in that other Contracting State during the aforesaid period or periods.

2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, surgeons, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19, 20 and 21, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that Contracting State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other Contracting State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned Contracting State, if :

- (a) the recipient is present in that other Contracting State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days during any taxable year or "previous year", as the case may be ; and
- (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of that other Contracting State ; and
- (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in that other Contracting State.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, remuneration in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that Contracting State.

Article 16

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

Article 17

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by an individual who is a resident of a Contracting State as an entertainer such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, and a musician, or as an athlete, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other Contracting State.

Such income shall, however, be exempt from tax in that other Contracting State if such activities are exercised by an individual who is a resident of the first-mentioned Contracting State pursuant to a special programme for cultural exchange agreed upon between the Governments of the two Contracting States.

2. Where income in respect of personal activities exercised in a Contracting State by an entertainer or an athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person who is a resident of the other Contracting State, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the first-mentioned Contracting State.

Such income shall, however, be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State if such activities are exercised pursuant to a special programme for cultural exchange agreed upon between the Governments of the two Contracting States.

Article 18

Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that Contracting State.

Article 19

1. (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State, or a political sub-division or a local authority thereof, to an individual in respect of services rendered to that Contracting State, or a political sub-division or a local authority thereof, in the discharge of functions of a governmental nature, shall be taxable only in that Contracting State.

(b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other Contracting State and the individual is a resident of that other Contracting State ; who :

- (i) is a national of that other Contracting State ; or
- (ii) did not become a resident of that other Contracting State solely for the purpose of performing the services.

2. (a) Any pension paid by, or out of funds to which contributions are made by, a Contracting State, or a political sub-division or a local authority thereof, to an individual in respect of services rendered to that Contracting State, or a political sub-division or a local authority thereof, shall be taxable only in that Contracting State.

(b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that other Contracting State.

3. The provisions of Articles 15, 16, 17 and 18 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof.

Article 20

Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned Contracting State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State, provided that such payments are made to him from outside that first-mentioned Contracting State.

Article 21

1. A professor or teacher who makes a temporary visit to a Contracting State for a period not exceeding two years for the purpose of teaching or conducting research at a university, college, school or other accredited educational institution, and who is, or immediately before such visit was, a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other Contracting State in respect of remuneration for such teaching or research.

2. This Article shall not apply to income from research if such research is undertaken not in the public interest but primarily for the private benefit of a specific person or persons.

Article 22

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that Contracting State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein or performs in that other Contracting State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effective connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles of this Convention and arising in the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

Article 23

1. The laws in force in either of the Contracting States shall continue to govern the taxation of income in the respective Contracting State except where express provisions to the contrary are made in this Convention.

2. Double taxation shall be avoided in the case of India as follows:

(a) Where a resident of India derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Japan, India shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the Japanese tax paid in Japan,

whether directly or by deduction. Such deduction in either case shall not, however, exceed that part of the income-tax (as computed before the deduction is given) which is attributable, as the case may be, to the income which may be taxed in Japan. Further, where such resident is a company by which surtax is payable in India, the deduction in respect of income-tax paid in Japan shall be allowed in the first instance from income-tax payable by the company in India and as to the balance, if any, from surtax payable by it in India.

(b) Where a resident of India derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, shall be taxable only in Japan, India may include this income in the tax base but shall allow as a deduction from the income-tax that part of the income-tax which is attributable, as the case may be, to the income derived from Japan.

3. Subject to the laws of Japan regarding the allowance as a credit against Japanese tax of tax payable in any country other than Japan:

(a) Where a resident of Japan derives income from India which may be taxed in India in accordance with the provisions of this Convention, the amount of Indian tax payable in respect of that income shall be allowed as a credit against the Japanese tax imposed on that resident. The amount of credit, however, shall not exceed that part of the Japanese tax which is appropriate to that income.

(b) Where the income derived from India is a dividend paid by a company which is a resident of India to a company which is a resident of Japan and which owns not less than 25 per cent either of the voting shares of the company paying the dividend, or of the total shares issued by that company, the credit shall take into account the Indian tax payable by the company payable the dividend in respect of its income.

(c) For the purposes of the credit referred to in subparagraphs (a) and (b) above, there shall be deemed to have been paid by the tax payer the amount which would have been paid as Indian tax under the laws of India and in accordance with this Convention if the Indian tax had not been reduced or relieved in accordance with the special incentive measures designed to promote economic development in India, effective on the date of signature of this Convention or which may be introduced in future in the Indian tax laws in modification of or in addition to the existing measures, provided that an agreement is made between the two Governments in respect of the scope of the benefit accorded to the tax payer by the said measures.

Article 24

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other Contracting State in the same circumstances are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other Contracting State than the taxation levied on enterprises of that other Contracting State carrying on the same activities.

This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

3. Except where the provisions of Article 9, paragraph 8 or Article 11, or paragraph 7 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned Contracting State.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned Contracting State are or may be subjected.

5. In this Article, the term "taxation" means taxes which are the subject of this Convention.

Article 25

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic laws of those Contracting States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of this Convention.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with the provisions of this Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic laws of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of this Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in this Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs of this Article.

Article 26

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by this Convention insofar as the taxation thereunder is not contrary to the provisions of this Convention, or for the prevention of fiscal evasion or fraud with respect to such taxes. Any information so exchanged shall be treated as secret and shall be disclosed only to persons or authorities including courts, involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the taxes covered by the Convention or the determination of appeals in relation thereto.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation :

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and the administrative practice of that or of the other Contracting State ;
- (b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State ; or

- (c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy.

Article 27

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consular officers under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 28

1. This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at Tokyo as soon as possible.

2. This Convention shall enter into force on the thirtieth day after the date of the exchange of instruments of ratification and shall have effect :

- (a) in Japan : as regards income for any taxable year beginning on or after the first day of January of the calendar year next following that in which this Convention enters into force; and
- (b) in India : as regards income for any "previous year" beginning on or after the first day of April of the calendar year next following that in which this Convention enters into force.

3. The Agreement between Japan and India for the Avoidance of Double Taxation in respect of Taxes on Income signed at New Delhi on January 5, 1960 shall terminate and cease to have effect in respect of income to which this Convention applies under the provisions of paragraph 2.

Article 29

This Convention shall continue in effect indefinitely but either Contracting State may, on or before the thirtieth day of June of any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force, give to the other Contracting State, through the diplomatic channel, written notice of termination and, in such event, this Convention shall cease to have effect :

- (a) in Japan : as regards income for any taxable year beginning on or after the first day of January of the calendar year next following that in which the notice of termination is given; and
- (b) in India : as regards income for any "previous year" beginning on or after the first day of April of the calendar year next following that in which the notice of termination is given.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Convention.

Done at New Delhi in duplicate on this Seventh day of March, 1989 in the Hindi, Japanese and English languages, all the three texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretations, the English text shall prevail.

For the Government

of the Republic of India.

Sd/-

(G. N. Gupta)

For the Government
of Japan.

Sd/-

(Eijiro Noda)

New Delhi, March 7, 1989

Excellency,

I have the honour to refer to sub-paragraph (c) of paragraph 3 of Article 23 of the Convention between the Government of the Republic of India and the Government of Japan for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income which was signed today and to confirm on behalf of the Government of the Republic of India, the following understanding reached between the Government of the Republic of India and the Government of Japan:

The measures set forth in the following sections of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) of India, are "the special incentive measures designed to promote economic development in India, effective on the date of signature of this Convention" referred to in the said sub-paragraph;

- (i) Section 10(15) (iv).—relating to exemption from tax on certain interest;
- (ii) Section 10A.—relating to special provision in respect of newly established industrial undertakings in free trade zones;
- (iii) Section 32AB.—relating to investment deposit account, etc. with respect to investment in plant and machinery etc.;
- (iv) Section 80HH.—relating to deduction in respect of profits and gains from newly established industrial undertakings or hotel business in backward areas;
- (v) Section 80I.—relating to deduction in respect of profits and gains from industrial undertakings after a certain date, etc.;

I have further the honour to request Your Excellency to be good enough to confirm the foregoing understandings on behalf of the Government of Japan.

I avail myself of this opportunity to extend to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

G. N. Gupta,
Chairman.

Central Board of Direct Taxes,
Ministry of Finance.

His Excellency Mr. Eihiro Noda.

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
of Japan to India.

New Delhi, March 7, 1989

Excellency,

I have the honour to acknowledge the receipt of Your Excellency's Note of today's date which reads as follows:

"I have the honour to refer to sub-paragraph (c) of paragraph 3 of Article 23 of the Convention between the Government of the Republic of India and the Government of Japan for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income which was signed today and to confirm, on behalf of the Government of the Republic of India, the following understanding reached between the Government of the Republic of India and the Government of Japan:

The measures set forth in the following sections of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) of India, are "the special incentive measures designed to promote economic development in India, effective on the date of signature of this Convention" referred to in the said sub-paragraph;

- (i) Section 10(15) (iv) relating to exemption from tax on certain interest;
- (ii) Section 10A.—relating to special provision in respect of newly established industrial undertakings in free trade zones;

(iii) Section 32AB.—relating to investment deposit account, etc. with respect to investment in plant and machinery etc.;

(iv) Section 80HH.—relating to deduction in respect of profits and gains from newly established industrial undertakings or hotel business in backward areas;

(v) Section 80I.—relating to deduction in respect of profits and gains from industrial undertakings after a certain date, etc.;

I have further the honour to request Your Excellency to be good enough to confirm the foregoing understanding on behalf of the Government of Japan."

I have further the honour to confirm the understanding contained in Your Excellency's Note, on behalf of the Government of Japan.

I avail myself of this opportunity to extend to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

Eihiro Noda.

Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary of Japan
to India.

His Excellency Mr. G. N. Gupta,
Chairman,

Central Board of Direct Taxes,
Ministry of Finance.

New Delhi, March 7, 1989

Excellency,

I have the honour to refer to the Convention between the Government of Japan and the Government of the Republic of India for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income which was signed today and to confirm, on behalf of the Government of Japan, the following understanding reached between the two Governments :

1. With reference to sub-paragraph (b) of paragraph 1 of Article 2 of the Convention, any taxes which are identical or substantially similar to the surtax imposed under the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 but abolished subsequently, and which are imposed in India after the date of signature of the Convention shall be regarded as the identical or substantially similar taxes referred to in paragraph 2 of Article 2 of the Convention.

2. With reference to sub-paragraph (d) of paragraph 1 of Article 3 of the Convention, the term "tax" shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which the Convention applies or which represents a penalty imposed relating to these taxes.

3. With reference to sub-paragraph (e) of paragraph 1 of Article 3 of the Convention, in the case of India, the term "person" shall include a partnership and a Hindu Undivided Family.

4. With reference to paragraph 5 of Article 5 of the Convention, the term "services or facilities" referred to therein shall include the supply of plant and machinery on hire used or to be used in the exploration, exploitation or extraction of mineral oils.

5. It is understood that the provisions of paragraph 6 of Article 5 of the Convention shall apply to the use of facilities solely for the purpose of delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise or to the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of delivery unless sales of such goods or merchandise are effected in that other Contracting State.

New Delhi, March 7, 1989

6. With reference to paragraph 1 of Article 7 of the Convention, it is understood that by using the term "directly or indirectly attributable to that permanent establishment", profits arising from transactions in which the permanent establishment has been involved shall be regarded as attributable to the permanent establishment to the extent appropriate to the part played by the permanent establishment in those transactions. It is also understood that profits shall be regarded as attributable to the permanent establishment to the above-mentioned extent, even when the contract or order relating to the sale or provision of goods or services in question is made or placed directly with the overseas head office of the enterprise rather than with the permanent establishment.

7. With reference to paragraph 3 of Article 7 of the Convention, it is understood that in India the deductions in respect of the executive and general administrative expenses as referred to in the said paragraph shall be allowed in accordance with the domestic law of India, but such deductions shall in no case be less than what are allowable under the Indian Income-tax Act as effective on the date of signature of the Convention.

8. With reference to paragraph 3 of Article 7 of the Convention, no deduction shall be allowed in respect of amounts paid or charged (other than reimbursement of actual expenses) by a permanent establishment of an enterprise to the head office of the enterprise or any other offices thereof, by way of :

- (a) royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or for the use of know-how ;
- (b) commission or other charges, for specific services performed or for management ; and
- (c) interest on moneys lent to the permanent establishment; except where the enterprise is a banking institution.

9. With reference to Article 8 of the Convention,

- (i) interest on funds temporarily deposited in connection with the operation of ships or aircraft in international traffic shall be regarded as income from the operation of such ships or aircraft and the provisions of Article 11 shall not apply in relation to such interest ; and
- (ii) income from the operation of ships or aircraft includes income derived from the use, maintenance or rental of containers (including trailers and related equipment for the transport of containers) in connection with the transport of goods or merchandise in international traffic.

10. With reference to paragraph 5 of Article 8 of the Convention, if a local authority of India introduces any taxes of a character substantially similar to the enterprise tax in Japan after the date of signature of the Convention, the two Governments shall consult with a view to amending paragraph 5 of Article 8 on a reciprocal basis in such manner as may be considered appropriate.

I have further the honour to request Your Excellency to be good enough to confirm the foregoing understanding on behalf of Your Excellency's Government.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

Sd/-

Fujiro Noda

Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary of Japan to
India

His Excellency Mr. G. N. Gupta
Chairman,
Central Board of Direct Taxes,
Ministry of Finance.

Excellency.

I have the honour to acknowledge the receipt of Your Excellency's Note of today's date which reads as follows :

"I have the honour to refer to the Convention between the Government of Japan and the Government of the Republic of India for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income which was signed today and to confirm, on behalf of the Government of Japan, the following understanding reached between the two Governments :

1. With reference to sub-paragraph (b) of paragraph 1 of Article 2 of the Convention, any taxes which are identical or substantially similar to the surtax imposed under the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 but abolished subsequently, and which are imposed in India after the date of signature of the Convention shall be regarded as the identical or substantially similar taxes referred to in paragraph 2 of Article 2 of the Convention.

2. With reference to sub-paragraph (d) of paragraph 1 of Article 3 of the Convention, the term "tax" shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which the Convention applies or which represents a penalty imposed relating to these taxes.

3. With reference to sub-paragraph (e) of paragraph 1 of Article 3 of the Convention, in the case of India, the term "person" shall include a partnership and a Hindu Undivided Family.

4. With reference to paragraph 5 of Article 5 of the Convention, the term "services or facilities" referred to therein shall include the supply of plant and machinery on hire used or to be used in the exploration, exploitation or extraction of mineral oils.

5. It is understood that the provisions of paragraph 6 of Article 5 of the Convention shall apply to the use of facilities solely for the purpose of delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise or to the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of delivery unless sales of such goods or merchandise are effected in that other Contracting State.

6. With reference to paragraph 1 of Article 7 of the Convention, it is understood that by using the term "directly or indirectly attributable to that permanent establishment", profits arising from transactions in which the permanent establishment has been involved shall be regarded as attributable to the permanent establishment to the extent appropriate to the part played by the permanent establishment in those transactions. It is also understood that profits shall be regarded as attributable to the permanent establishment to the above-mentioned extent, even when the contract or order relating to the sale or provision of goods or services in question is made or placed directly with the overseas head office of the enterprise rather than with the permanent establishment.

7. With reference to paragraph 3 of Article 7 of the Convention, it is understood that in India the deductions in respect of the executive and general administrative expenses as referred to in the said paragraph shall be allowed in accordance with the domestic law of India, but such deductions shall in no case be less than what are allowable under the Indian Income-Tax Act as effective on the date of signature of the Convention.

8. With reference to paragraph 3 of Article 7 of the Convention, no deduction shall be allowed in respect of amounts paid or charged (other than reimbursement of actual expenses) by a permanent establishment of an enterprise to the head office of the enterprise or any other offices thereof, by way of :

- (a) royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or for the use of know-how ;

- (b) commission or other charges, for specific services performed or for management; and
- (c) interest on moneys lent to the permanent establishment; except where the enterprise is a banking institution.

9. With reference to Article 8 of the Convention.

- (i) interest on funds temporarily deposited in connection with the operation of ships or aircraft in international traffic shall be regarded as income from the operation of such ships or aircraft and the provisions of Article 11 shall not apply in relation to such interest; and
- (ii) income from the operation of ships or aircraft includes income derived from the use, maintenance or rental of containers (including trailers and related equipment for the transport of containers) in connection with the transport of goods or merchandise in international traffic.

10. With reference to paragraph 5 of Article 8 of the Convention, if a local authority of India introduces any taxes of a character substantially similar to the enterprise tax in Japan after the date of signature of the Convention, the two Governments shall consult with a view to amending para-

graph 5 of Article 8 on a reciprocal basis in such manner as may be considered appropriate.

I have further the honour to request Your Excellency to be good enough to confirm the foregoing understanding on behalf of Your Excellency's Government."

I have further the honour to confirm the understanding contained in Your Excellency's Note, in behalf of the Government of the Republic of India.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

Sd/-

G. N. Gupta,
Chairman,
Central Board of Direct Taxes,
Ministry of Finance.

His Excellency Mr. Eijiro Noda,
Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary of Japan to
India.

[No. 8587/F. No. 506/69/81-FTD]

P. K. APPACHOO, Jt. Secy.